6. Scooters India Ltd.
7. Triveni Structurals Ltd.
8. Bharat Process and Mechanical Engineering Ltd.
9. Tannery and Footwear Corporation Ltd.
10. National Instruments Ltd.
11. Weighbird India Ltd.
12. Tyre Corporation of India Ltd.
13. Bharat Breaks and Valves Ltd.
14. Bhart Opthalmic Glass Ltd.
15. Braithwait and Company Ltd.

Orders placed with instrumentation Limited, Kota

398. SHRIMATI CHANDRAKALA PANDEY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that modernistaon of Insrumentation Limited, Kota was done to cater to the needs of CDOT of Telecom Department, if so, what are the reasons that only 8 crores orders were placed from Department of Telecom against the planned order of 100 crores; and

(b) what action is being taken by the Ministry of Industry regarding placing of sufficient orders on the Instrumentation Limited, Kota by Ministry of Communications?

THE MINISTER OF STATE IN MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) and (b) Instrumentation Ltd., Kota (IL) had had identified telecommunication as the thrust area during the Eighth plan period itself for diversification and growth of company as telecommunication had the vast potential as per plans of the Department of Telecommunications.

In the year 1993-94 the company had received orders worth Rs. 10 crores on competitive bidding. Department of Telecommunications had been requested to place orders for C-DOT technology based Telephone Exchanges. However, they are not able to place orders to the extent desired by IL. The orders are limited to the extent permitted by tender conditions.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का बंद होना

399. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला :**
श्री ईश्वर दत्त यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधीन कौन-कौन से एकक बन्द कर दिए गए हैं/किए जाने की सम्भावना है ;

(ख) इनमे से प्रत्येक एकक को अब तक कितना नुकसान हुआ है ;

(ग) इन एककों को पुनः चालू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) सरकार इन एककों के प्रभावित कर्मचारियों को किस प्रकार पुनः रोजगार प्रदान करने का विचार रखती है ?

उद्यो. मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक एककों को समय समय पर यथा संशोधित रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम (विशेष प्रावधान), 1985 के प्रावधान के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा गया है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल ने संबद्ध उच्च न्यायालय से नेशनल बाइसाइकिल कारपोरेशन लि०, ब्रिटिश इण्डिया कार्पो लि० और एल्गिन मिल्स कम्पनी लि० को बन्द करने की अनुशंसा की है। 31-3-1993 की अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है जिसके अनुसार सरकारी क्षेत्र के उद्यम वार संचयी घाटे का ब्यौरा दिनांक 23-2-94 को संसद में प्रस्तुत किये गये लोक उद्यम सर्वेक्षण 1992-93 के खण्ड III में संक्षिप्त लाभ तथा हानि लेखे में दिया गया है ।